बुधवार
18 नवम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 297
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

'नरबलि' बयान पर सियासी 'संग्राम'

◆विधायक हरीश धामी के बयान से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा बयानों की तल्खी सुर्खियां बटोर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ही तेज है, लेकिन अब विधायक हरीश धामी के नरबलि संबंधी बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। धामी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक को नर पिशाच तक बता दिया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है।



◆भाजपा ने बताया नर पिशाच, कांग्रेस के सामने भी असहज स्थिति
◆शब्दों की मर्यादा व राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ी

दरअसल, हरीश धामी के बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक सोच और भाषा का उदाहरण बताते हुए हमला बोला है। भाजपा की ओर से इस्तेमाल किए गए नर पिशाच जैसे शब्दों ने विवाद को और तीखा कर दिया। अब सवाल केवल धामी के बयान की व्याख्या का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विरोध की आड़ में सार्वजनिक संवाद किस स्तर तक गिर सकता है, यह भी बहस का विषय बन गया है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा जहां कांग्रेस को गैरजिम्मेदार और मुद्दाविहीन बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। ऐसे माहौल में हरीश धामी का बयान भाजपा के लिए कांग्रेस पर हमला करने का एक नया अवसर बन गया है।

हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। किसी विधायक के बयान पर राजनीतिक असहमति जताना विपक्षी लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जवाब में व्यक्तिगत और अपमानजनक विशेषणों का इस्तेमाल क्या राजनीतिक स्तर को और नीचे नहीं ले जाता? सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के राजनीतिक दल जनता के वास्तविक मुद्दों पर बहस करने के बजाय एक-दूसरे के बयानों को ही चुनावी हथियार बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? उत्तराखंड इस समय बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली तक कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर सत्ता और विपक्ष दोनों से जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विमर्श का केंद्र बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणियों और विवादित बयानों पर सिमटता जा रहा है।

हरीश धामी का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक जवाबदेही और सार्वजनिक भाषा के लिहाज से चर्चा के दायरे में है। लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि क्या राजनीतिक विरोध का मतलब विरोधी को किसी भी विशेषण से नवाज देना है? लोकतंत्र में बयान की आलोचना तथ्यों और तर्कों से होनी चाहिए, न कि अपमानजनक शब्दों से। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उसके विधायक का बयान किस संदर्भ में दिया गया और क्या पार्टी उस भाषा तथा उसके राजनीतिक निहितार्थ से सहमत है। वहीं भाजपा को भी यह बताना होगा कि वह प्रदेश की राजनीति को विकास और जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ाना चाहती है या फिर व्यक्तिगत हमलों की प्रतिस्पर्धा में ही उलझाए रखना चाहती है।

दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब बयान ही बयान हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब गायब हैं। एक तरफ विधायक का नरबलि वाला बयान विवाद खड़ा करता है तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल की ओर से नर पिशाच जैसे शब्द राजनीतिक मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े प्रदेश में असली चुनौती एक-दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि जनता के सामने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक हिसाब रखने की है। वरना 2027 की चुनावी लड़ाई में मुद्दे पीछे छूटेंगे और नेताओं के विवादित बयान ही राजनीति का चेहरा बन जाएंगे।

पीआरडी जवानों ने किया सीएम आवास कूच

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर प्रदेशभर से करीब 5 से 6 हजार प्रांतीय रक्षक दल जवान देहरादून पहुंचे। जिन्होने अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया। जिन्हे पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिग लगाकर सीएम आवास से पहले लोकभवन के पास रोक लिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।

पीआरडी जवान 365 दिन रोजगार की गारंटी और मानदेय बढ़ाकर होमगार्ड जवानों के बराबर करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर के पीआरडी जवान आज अपनी मांगों को लेकर देहरादून के परेड मैदान में एकत्र हुए। जहां से उन्होने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पीआरडी जवानों की हजारों की तादाद में संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन एलर्ट मोड पर आ गया और उन्होने उन्हे हाथी बड़कला के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोकना चाहा। लेकिन पीआरडी

◆365 दिन रोजगार और बढ़े मानदेय की मांग

जवान उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गये। जिसके बाद पुलिस द्वारा फिर रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां भी पीआरडी जवान नहीं रूके। जिस पर पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता हो गये और उन्होने इस बार भारी पुलिस बल की सहायता से पीआरडी जवानों को मुख्यमंत्री आवास से पहले लोकभवन



के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गयां। इस दौरान पुलिस और पीआरडी जवानो की आपसी झड़प की बात भी सामने आयी है। जब पीआरडी जवान नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर उन्हे रोकना पड़ा। जिस पर पीआरडी जवान वहीं धरने पर बैठ गये। समाचार लिखे जाने तक पीआरडी जवानों को धराना प्रदर्शन जारी था।

दून वैली मेल

संपादकीय

अब कान्हा की नगरी

भारतीय राजनीति में चुनावी मुद्दे कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल अपनी जरूरत के हिसाब से बार-बार जीवित कर देते हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भाजपा ने कान्हा की नगरी से अपनी चुनावी रणनीति को नई धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। मथुरा में हुई दो दिवसीय चिंतन बैठक ने साफ कर दिया है कि भाजपा आगामी चुनाव में विकास और सुशासन के साथ धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने जा रही है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले भाजपा को मथुरा की याद इतनी शिद्दत से क्यों आ रही है? क्या यह केवल धार्मिक आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गणित काम कर रहा है? दरअसल, भाजपा के सामने 2027 की चुनौती केवल सत्ता में वापसी की नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की है। पिछले चुनावों में पार्टी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ने इस राजनीतिक विमर्श को नई ऊंचाई दी। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास को भी इसी सांस्कृतिक राजनीति के विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब मथुरा के जरिए इस पूरी राजनीतिक परिकल्पना को एक और पड़ाव तक ले जाने की कोशिश दिखाई दे रही है। मथुरा की बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि, समान नागरिक संहिता, विकास, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रवाद को चुनावी एजेंडे के प्रमुख विषयों के रूप में सामने रखा गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की काट तलाशने पर भी मंथन हुआ है। यानी भाजपा केवल धार्मिक मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा रही, बल्कि उसके सहारे सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी नए सिरे से साधना चाहती है। इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिस तरह राजनीतिक झटका लगा, उसने पार्टी को यह सोचने पर मजबूर किया कि केवल अपने पुराने चुनावी नारों और संगठनात्मक ताकत के भरोसे आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। विपक्ष ने संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और पीडीए के सवालों को जिस तरह चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाया, उससे भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी हुई। अब मथुरा के रास्ते इस विमर्श की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीति में प्रतीकों की भी एक सीमा होती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है। उससे जुड़ी जनभावनाओं और आंदोलन का अपना अलग संदर्भ रहा है। मगर हर चुनाव में धार्मिक प्रतीकों को ही राजनीतिक सफलता का सबसे प्रभावी हथियार मान लेना लोकतंत्र और विकास की व्यापक जरूरतों को सीमित करने जैसा होगा। जनता मंदिर और आस्था का सम्मान करती है, लेकिन वह रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने भविष्य को लेकर भी जवाब चाहती है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह मथुरा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को राजनीतिक मुद्दा बनाने के साथ-साथ सरकार के कामकाज का हिसाब भी दे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, युवाओं की आकांक्षाएं, किसानों की समस्याएं और स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन से जुड़ी शिकायतें ऐसे सवाल हैं, जिन्हें केवल धार्मिक विमर्श के सहारे किनारे नहीं किया जा सकता। विपक्ष भी इस बार केवल भाजपा के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जनता के वास्तविक मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाने में सफल रहा तो मुकाबला दिलचस्प होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व केवल मंदिर और धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। गीता का कर्मयोग, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, धर्म की स्थापना और लोककल्याण का संदेश उनकी व्यापक विरासत है। कृष्ण की धरती से राजनीति करने वाले दलों को उनके संदेश के इस पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। धर्म यदि राजनीति को नैतिकता और जनकल्याण की दिशा देता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यदि वह केवल चुनावी ध्रुवीकरण का औजार बनकर रह जाए तो उसकी सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मथुरा में भाजपा का मंथन दरअसल 2027 के चुनाव से पहले अपने पुराने राजनीतिक हथियारों को नए सिरे से धार देने की कवायद है। पार्टी जानती है कि अयोध्या का राजनीतिक प्रभाव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। अब वह मथुरा को भी उसी व्यापक चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाना चाहती है। मगर अयोध्या की सफलता को मथुरा में दोहराने की राजनीतिक गणित इतनी सरल नहीं है। हर चुनाव के मुद्दे, परिस्थितियां और मतदाताओं की अपेक्षाएं अलग होती हैं। आखिरकार लोकतंत्र में जीत केवल भावनाओं के सहारे नहीं मिलती, उसे जनता के भरोसे से हासिल करना पड़ता है। मंदिर का सवाल अपनी जगह है, लेकिन जनता के जीवन से जुड़े सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यदि मथुरा के रास्ते जीत की तलाश कर रही है तो उसे यह भी समझना होगा कि मतदाता केवल आस्था से नहीं, अपने अनुभवों और अपेक्षाओं से भी मतदान करता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भाजपा के लिए चुनावी संजीवनी बन सकता है, लेकिन सत्ता की राह केवल मंदिर के दरवाजे से होकर नहीं गुजरती। उस राह पर रोजगार, महंगाई, किसान, युवा और आम आदमी के सवाल भी खड़े हैं। 2027 में असली परीक्षा इसी बात की होगी कि भाजपा इन सवालों का जवाब देती है या एक बार फिर चुनावी विमर्श को आस्था के इर्द-गिर्द समेटने में सफल होती है।

आबादी की गिनती से खुलेंगी 'परते'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। करीब डेढ़ दशक के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही जनगणना इस बार प्रदेश के लिए महज आबादी की गिनती का सरकारी अभियान नहीं है। इसके आंकड़े उत्तराखंड की बदलती सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तस्वीर का आईना बनने जा रहे हैं। पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन, मैदानी जिलों में बढ़ते जनसंख्या दबाव,

◆पहाड़ के बदलते सामाजिक व राजनीतिक समीकरण
◆पलायन से लेकर जातीय संरचना तक पर रहेगी नजर
◆अब पहाड़ में पलायन की असली तस्वीर आएगी सामने
◆पहाड़-मैदान के बीच बढ़ती खाई की साफ होगी तस्वीर

गांवों के खाली होते घर, शहरों की ओर बढ़ते रुझान और जातीय संरचना में आ रहे बदलावों के बीच इस जनगणना के नतीजों का विशेष महत्व होगा।

प्रदेश को जनगणना के लिए 34,443 गणना ब्लाकों में विभाजित किया गया है। इस विशाल अभियान के लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी बड़े स्तर पर पूरी की जा रही है। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक डिजिटल स्वगणना का विकल्प उपलब्ध है, जबकि एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक संशोधन का चरण चलेगा। पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि को जनगणना की संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है।

उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पहाड़ से पलायन है। राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोगों का मैदानी क्षेत्रों की ओर जाना जारी है। कई गांव ऐसे हैं जहां कभी आबाद रहने वाले घर अब खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी जैसे शहरी क्षेत्रों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जनगणना में जन्मस्थान, पूर्व निवास स्थान और पलायन के कारणों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने लोग अपने मूल निवास से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं और इसके पीछे रोजगार, शिक्षा, विवाह अथवा अन्य कारण कितने जिम्मेदार हैं।

यह आंकड़े सरकार के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी टिक क्यों नहीं पा रही है? जिन गांवों को पलायन रोकने के लिए आदर्श गांव और रिवर्स पलायन जैसी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश हुई, वहां वास्तविक बदलाव कितना आया है? जनगणना के आंकड़े इन दावों की पड़ताल

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

आंकड़े बताएंगे, 26 साल में कितना बदला उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यह पहला ऐसा बड़ा अवसर है जब प्रदेश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर को नए सिरे से समझने के लिए व्यापक आंकड़े उपलब्ध होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से अब तक प्रदेश में बड़े बदलाव हुए हैं। देहरादून का विस्तार हुआ है, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में शहरीकरण बढ़ा है, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में नई जनगणना के आंकड़े केवल यह नहीं बताएंगे कि उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी समझने का अवसर देंगे कि प्रदेश की आबादी कहां बढ़ रही है, कहां घट रही है और किन सामाजिक-आर्थिक कारणों से यह बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन आंकड़ों को केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित रखेगी या फिर इनके आधार पर उत्तराखंड के विकास का नया खाका तैयार करेगी? क्योंकि जिस राज्य की स्थापना पहाड़ के विकास, स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के संकल्प के साथ हुई थी, उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए जनगणना से बेहतर अवसर शायद ही कोई दूसरा हो। जनगणना इस बार उत्तराखंड की केवल आबादी नहीं गिनेगी, बल्कि राज्य गठन के 26 वर्षों के विकास का हिसाब भी सामने रखेगी। पहाड़ में कितने घर खाली हुए, कितने लोग मैदानों में बसे, सामाजिक संरचना कितनी बदली और विकास का लाभ किस क्षेत्र तक पहुंचा, इन सवालों के जवाब ही उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।

पहले 'पर्दे' के पीछे अब 'मीडिया' के सामने

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक चेतना के केंद्र में है। करीब चार साल पुराने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्य दोषी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की अचानक सक्रियता ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपने बेटे का बचाव करने वाले विनोद आर्य पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए और उन्होंने न केवल एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए, बल्कि अंकिता की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताते हुए उसके माता-पिता और मित्र पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। यही नहीं, उन्होंने अंकिता और उसके मित्र की कथित निजी व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सार्वजनिक कर दिए।

विनोद आर्य की इस प्रेस वार्ता ने मामले को फिर से गरमा दिया है। लेकिन इस बार सवाल केवल उनके दावों का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि आखिर एक दोषसिद्ध अपराधी के पिता को इतने वर्षों बाद अचानक अपने बेटे के बचाव में सामने आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज अपने बेटे के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश है या फिर इस प्रकरण में किसी नए राजनीतिक नैरेटिव को खड़ा करने की कवायद? 15 नवंबर को हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में विनोद आर्य ने दावा किया कि उनके बेटे पुलकित आर्य को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया। उन्होंने अंकिता और उसके मित्र पुष्पदीप के बीच हुई कथित 4,085 पन्नों की व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। उनका दावा था कि इन चौट में उनके बेटे के खिलाफ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिससे

◆अंकिता केस में विनोद आर्य की सक्रियता के मायने क्या
◆पुलकित आर्य के बाद विनोद आर्य भी सवालों के घेरे में
◆निजी चेट सार्वजनिक करने से भड़क गया अब आक्रोश
◆माता-पिता ने मांगा नार्को टेस्ट व काल डिटेल की जांच

हत्या के आरोप की पुष्टि होती हो। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की।

लेकिन विनोद आर्य के इन दावों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जिस मामले में अदालत तीन आरोपियों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, उसमें अब मृतका के चरित्र, उसके पारिवारिक संबंधों और निजी बातचीत को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी मृत बेटी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक करना न्याय की लड़ाई है या उसकी गरिमा को एक बार फिर कठघरे में खड़ा करना? विनोद आर्य की प्रेस वार्ता के बाद अंकिता के माता-पिता ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विनोद आर्य का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने और घटना वाली रात की उनकी कॉल डिटेल रिकार्ड की जांच करने की मांग की है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने आरोप लगाया है कि घटना के आसपास विनोद आर्य का दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आना-जाना रहा था। उन्होंने सीबीआई से इस पहलू की जांच करने की मांग की है।

अंकिता के माता-पिता का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, वह प्रदेशभर में आंदोलन जारी रखेंगे। इस मांग ने अब जांच का दायरा और व्यापक करने की बहस छेड़ दी है। हालांकि विनोद आर्य का नार्को टेस्ट या काल डिटेल की जांच कराने की मांग अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। इसकी जरूरत और वैधानिकता का निर्धारण जांच एजेंसी और सक्षम कानूनी प्राधिकारी को करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और गंभीर पहलू है। अंकिता की कथित निजी चौट सार्वजनिक किए जाने के विरोध में पहाड़ी महासभा ने हरिद्वार नगर कोतवाली में विनोद आर्य के खिलाफ शिकायत दी है। महासभा का कहना है कि एक मृत युवती की निजी बातचीत सार्वजनिक करना उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर ये चौट किस स्रोत से प्राप्त हुईं और इन्हें सार्वजनिक करने का अधिकार किसने दिया?

यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। यदि विनोद आर्य के पास वर्ष 2023 से यह दस्तावेज मौजूद थे तो उन्होंने इतने लंबे समय तक इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर



छात्र-छात्राओं को दिया जनजाति अधिकारों, महिला सशक्तिकरण व जनजाति युवा वर्ग पर आधुनिकीकरण का प्रभाव संबंधी व्याख्यान

संवाददाता

रुद्रपुर। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में संयोजक प्रोफेसर आशा राणा ने जनजातीय गौरव दिवस की आवश्यकता और उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए छात्र-छात्राओं को जनजाति अधिकारों महिला सशक्तिकरण जनजाति युवा वर्ग पर आधुनिकीकरण का प्रभाव संबंधी व्याख्यान प्रस्तुत किया इस कार्यक्रम में तीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सर्वजीत सिंह द्वारा किया गया

पोस्टर प्रतियोगिता में इकरा बिपाशा बी ए 5 सेमेस्टर ने प्रथम स्थान,हेमलता एम ए 3 सेमेस्टर ने द्वितीय स्थान,श्याम सिंह बी ए 5 सेमेस्टर,आरती बी ए 5 सेमेस्टर ने तृतीय स्थान तथा मोनू राजभर एम ए 1 सेमेस्टर ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया।

भाषण प्रतियोगिता में टीना दिवाकर एम ए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा ने प्रथम स्थान और नीतू मौर्या एम तृतीय सेमेस्टर की छात्रा ने द्वितीय स्थान तथा तरुण बिष्ट बी ए पंचम सेमेस्टर के छात्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

निबंध प्रतियोगिता मे टीना दिवाकर एम तृतीय सेमेस्टर की छात्रा ने प्रथम स्थान और नीतू मौर्या एम तृतीय सेमेस्टर की छात्रा ने द्वितीय स्थान तथा रूपा बी ए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा ने तृतीय स्थान तथा रजत कुमार बीएस सी प्रथम सेमेस्टर के छात्र ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन जनजातीय संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण की शपथ के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रो० दीपा वर्मा, डॉ० सुमन कुमार, डॉ आर ए खान, डॉ अजय गिरी आदि महाविद्यालय फैकल्टी तथा छात्र छात्रा उपस्थित रहे।

बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं, स्कूल बसों की हुई चैकिंग

हमारे संवाददाता

पौड़ी। लगातार हो रहे सड़क हादसों और स्कूली बच्चों की जान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। श्रीनगर सहित पूरे जनपद में सुबह से ही पुलिस की टीमें सड़क पर उतर गई और स्कूल बसों, वैन, कार, बाइक और स्कूटी की गहन तलाशी ली गयी हैं।

स्कूल बसों की जांच के दौरान पुलिस सबसे पहले यह भी देख रही है कि बस में आग बुझाने वाला यंत्र काम कर रहा है या नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयां सही हैं या नहीं, आपातकाल के समय बाहर निकलने का रास्ता खुलता है या नहीं और बस में तय संख्या से ज्यादा बच्चे तो नहीं बैठाए जा रहे। बस के कागज, फिटनेस, बीमा, परमिट और चालक का लाइसेंस भी बारीकी से परखा जा रहा है। जहां भी कमी मिल रही है, वहां तुरंत चालान हो रहा है और कई वाहनों को मौके पर ही रोक दिया जा रहा है। दोपहिया वाहनों पर भी पुलिस की नजर सबसे ज्यादा है। अब बाइक या स्कूटी चलाने वाला ही नहीं, उसके पीछे बैठा व्यक्ति भी बिना हेलमेट के पकड़ा गया तो चालान से नहीं बचेगा। तीन सवारी बैठाना, बिना लाइसेंस गाड़ी दौड़ाना और तेज रफ्तार में वाहन चलाना भी पुलिस के रडार पर है। सबसे सख्त रुख नाबालिग चालकों को लेकर है। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका वाहन तुरंत सीज होगा और उसके माता-पिता व वाहन मालिक को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिसमें भारी जुर्माने के साथ जेल तक का प्रावधान है।



वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

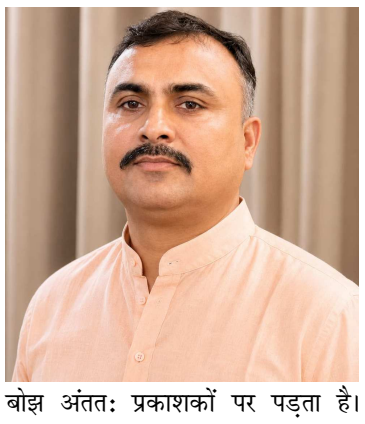
लघु-मध्यम समाचार पत्रों पर जीएसटी का बोझ खत्म करने की पहल

न्यूजप्रिंट, कागज, स्याही और प्रिंटिंग सामग्री को जीएसटी मुक्त करने की मांग

संवाददाता

नई दिल्ली/लखनऊ। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों पर पड़ रहे जीएसटी के आर्थिक बोझ से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण पहल करने का आग्रह किया है।

आज यहां देश के लघु-मध्यम समाचार पत्रों की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति और बढ़ती प्रकाशन लागत का मुद्दा अब भारतीय प्रेस परिषद के स्तर पर उठाया गया है। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों पर पड़ रहे जीएसटी के आर्थिक बोझ से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे इस विषय में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) को पत्र लिखकर न्यूजप्रिंट और समाचार पत्रों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री को जीएसटी से मुक्त करने अथवा विशेष कर राहत देने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुशंसा करें। त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा है कि समाचार पत्रों की बिक्री पर जीएसटी की शून्य दर लागू होने के बावजूद अखबारों के प्रकाशन में इस्तेमाल होने वाले न्यूजप्रिंट, कागज, स्याही, प्रिंटिंग प्लेट और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद पर प्रकाशकों को जीएसटी चुकाना पड़ता है। समाचार पत्रों की आपूर्ति से जुड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैधानिक सीमाओं के कारण इस कर का आर्थिक



बोझ अंततः प्रकाशकों पर पड़ता है। छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि वे सीमित पूंजी और सीमित विज्ञापन संसाधनों के सहारे अपना प्रकाशन जारी रखते हैं। पत्र में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि जब समाचार पत्र प्रकाशक पाठकों से अखबार की बिक्री पर अलग से जीएसटी नहीं वसूलते, तो अखबार तैयार करने के लिए खरीदी जाने वाली आवश्यक सामग्री पर चुकाए गए कर का पूरा आर्थिक भार प्रकाशक ही क्यों उठाए? त्रिपाठी के मुताबिक, बड़े मीडिया समूहों की तुलना में छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के पास पूंजी, विज्ञापन और आय के सीमित स्रोत होते हैं। कागज की बढ़ती कीमतें, छपाई, वितरण, कर्मचारियों के वेतन और अन्य संचालन खर्च पहले ही उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में प्रकाशन सामग्री पर लगने वाला जीएसटी उनकी आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि छोटे समाचार पत्र केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र में आम नागरिक की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय समस्याओं, सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को सामने लाने में इन समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। त्रिपाठी ने अपने पत्र में आगाह किया है कि आर्थिक दबाव के कारण यदि छोटे और मध्यम समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद होता है या उनकी प्रसार क्षमता प्रभावित होती है, तो इसका नुकसान केवल प्रकाशकों और पत्रकारों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर उन क्षेत्रों की जनता पर पड़ेगा, जहां स्थानीय समाचार पत्र ही आम लोगों की समस्याओं और उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाए तथा छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर राहत देने की पहल की जाए। त्रिपाठी की इस पहल ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि जब समाचार पत्र लोकतंत्र में जनहित और जनजागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनकी छपाई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री पर कर का ऐसा बोझ क्यों हो, जो छोटे प्रकाशकों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दे? अब देखना होगा कि भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष इस मांग पर क्या पहल करती हैं और जीएसटी काउंसिल तक यह मुद्दा किस रूप में पहुंचता है।

स्कूलों की तीन बसों में मिलीं खामियां, चालान किए

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। स्कूली बच्चों और यात्रियों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह के नेतृत्व में परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने गुलाबराय स्थित अनूप नेगी मेमोरियल स्कूल और रैतौली स्थित क्रिस ज्योति एकेडमी की स्कूल बसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनूप नेगी मेमोरियल स्कूल की तीन बसों में कमियां मिलीं। इनमें प्राथमिक उपचार पेटी, जरूरी लाइटों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं मिलीं। इस पर परिवहन विभाग ने तीनों बसों के चालान किए।इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन को वाहनों में जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पायल सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा विद्यालय प्रबंधन, वाहन चालकों, अभिभावकों और संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूल बसों और वैन में सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य चालान करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधन और वाहन संचालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। 16 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल बसों, वैन, कैब और यात्री बसों की जांच की जाएगी।

आईटीएम कॉलेज के पांच क्रिकेटरों का विश्वविद्यालय की नॉर्थ जोन टीम में चयन

संवाददाता

देहरादून। आईटीएम कॉलेज के पांच क्रिकेटरों का विश्वविद्यालय की नार्थ जोन टीम में चयन हो गया।

आज यहां आईटीएम कॉलेज के चेयरमैन निशांत थपलियाल ने बताया कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 6 नवंबर 2026 तक आईटीएम कॉलेज, देहरादून की मेजबानी में जीएसआर क्रिकेट अकादमी एवं रामराज क्रिकेट अकादमी में किया गया। प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून एवं पौड़ी सहित विभिन्न जनपदों के 15 महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया।

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश एवं आईटीएम कॉलेज, देहरादून के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में आईटीएम कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की नॉर्थ जोन क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें आईटीएम कॉलेज के पांच खिलाड़ियों शिवम, अमन, अमित, गोचर कपिल एवं अंश मंडवाल ने स्थान बनाया है। चयनित खिलाड़ी आगामी नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

नॉर्थ जोन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए विश्वविद्यालय की टीम 19 नवंबर को लखनऊ के लिए रवाना होगी, जबकि मुकाबले 20 नवंबर से शुरू होंगे।

आईटीएम कॉलेज के चेयरमैन निशांत थपलियाल ने पांच खिलाड़ियों के विश्वविद्यालय की नॉर्थ जोन टीम में चयन को संस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। यह पूरे संस्थान के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि चयनित खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे।

गन्ने की फसल काटकर नुकसान पहुंचाने पर तीन नामजद

संवाददाता

देहरादून। गन्ने की फसल काटकर नुकसान पहुचाने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इंजिनियर एन्क्लेव निवासी जगमोहन सिंह चौहान ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी ईस्ट होम टाउन माजरा में कृषि भूमि है जिसमें गन्ने की फसल लगी हुई थी। आज जब वह वहां पर गया तो उसकी गन्ने की फसल गायब थी। आसपास के लोगों ने बताया कि निशा गोस्वामी, जब्बार व शमशाद अपने सात आठ साथियों के साथ उसके खेत में आये थे तथा गन्ने की फसल काटकर ले गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

दो नाबालिग लापता

संवाददाता

देहरादून। दो नाबालिगों के लापता होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पटेलनगर निवासी दो लोगों ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी 14 व 15 साल की नाबालिग बेटियों घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। उन्होंने दोनों को सभी सम्भावित स्थानों पर तलाश किया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मकान का ताला तोड अभूषण चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड वहां से अभूषण चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएमएस रोड निवासी ब्रिजेश कुमार चौधरी ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गया था। आज जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके मकान का ताला टूटा हुआ था। अन्दर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर उसके यहां से अभूषण चोरी करके ले गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

घर में घुसकर मारपीट में व्रत्तास मुकदमें दर्ज

संवाददाता

देहरादून। घर में घुसकर मारपीट करने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कांवली रोड निवासी सुलेमान ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पडोस में रहने वाले दानिश, इकरार अली, इकदार अली, अमिताभ अली, समीर अपने अन्य साथियों के साथ उसके घर में घुस आये और उसके साथ गाली गलौच शुरू कर दी। उसने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब आसपास के लोग उसको बचाने आये तो हमलावर उसको जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। वहीं दूसरी तरफ स्वातिका प्रवीन ने आमिर खन, सलमान, व सुलेमान के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

आईटीबीपी जवान लापता

संवाददाता

देहरादून। आईटीबीपी के जवान के लापता होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटीबीपी के अधिकारी ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनका एक जवान बिना बताये कहीं चला गया। उन्होंने उसको काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

खुखरी से हमला कर किया घायल

संवाददाता

देहरादून। खुखरी से हमला कर घायल करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यनगर निवासी ओमप्रकाश ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पुत्र ब्रहमावाला खाले किसी काम से गया था। जहां पर हर्षित, देव व सौरभ के बडे भाई ने उसके बेटे पर खुखरी से हमला कर उसको गम्भीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

किडनी वाले मरीज को नहीं खाना चाहिए केला ?





किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी ही करता है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद उससे जो गंदगी निकलता है वही टॉयलेट में बदल जाता है। शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस से लेकर बॉडी में आयरन को बैलेंस करने का काम किडनी का ही होता है। अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है तो हाई बीपी, डायबिटीज, दिल की बीमारी, हेपेटाइटिस सी वायरस और एचआईवी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। जब किडनी खराब हो जाता है तो शरीर का आधे से ज्यादा फंक्शन में गड़बड़ी होने लगता है। किडनी के मरीज को कुछ खास तरह के फूड आइटम को खाने से परहेज करना चाहिए।

गहरे रंग का सोडा

सोडा में कैलोरी और चीनी के अलावा पोटैशियम भी होता है। कई खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने, शेल्फ जीवन को बढ़ाने और मलिनकिरण को रोकने के लिए प्रसंस्करण के दौरान फॉस्फोरस मिलाया जाता है। आपका शरीर प्राकृतिक, पशु- या पौधे-आधारित फास्फोरस की तुलना में इस अतिरिक्त फास्फोरस को बेहतर ढंग से अवशोषित करता है।

एवोकैडो : एवोकैडो को अक्सर उनके हृदय-स्वस्थ वसा, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट सहित कई पोषण गुणों के लिए आहार में शामिल किया जाता है। जबकि एवोकाडो आम तौर पर आहार में एक स्वस्थ अतिरिक्त है, गुर्दे की बीमारी वाले व्यक्तियों को इनसे परहेज करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एवोकाडो पोटेशियम का बहुत समृद्ध स्रोत है।

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जैसे सूप, सब्जियाँ और बीन्स, अक्सर उनकी कम लागत और सुविधा के कारण खरीदे जाते हैं। हालांकि, अधिकांश डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में सोडियम होता है, क्योंकि उनके शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए नमक को परिरक्षक के रूप में जोड़ा जाता है। डिब्बाबंद वस्तुओं में पाए जाने वाले सोडियम की मात्रा के कारण, अक्सर यह सिफारिश की जाती है कि गुर्दे की बीमारी वाले लोग इसके सेवन से बचें या इसे सीमित करें।

मल्टीग्रेन ब्रेड : किडनी की बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड फायदेमंद हो सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, आमतौर पर परिष्कृत, सफेद आटे की ब्रेड की तुलना में साबुत गेहूं की ब्रेड की सिफारिश की जाती है। साबुत गेहूं की ब्रेड अधिक पौष्टिक विकल्प हो सकती है। मुख्यतः इसकी उच्च फाइबर सामग्री के कारण हालांकि, किडनी की बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए व्हाइट ब्रेड की तुलना में मल्टीग्रेन ब्रेड ज्यादा फायदेमंद है।

ब्राउन राइस : ब्राउन राइस में फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और इसे किडनी आहार पर नियंत्रित या सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। सफेद चावल, बुलगुर और एक प्रकार का अनाज अच्छे विकल्प हैं। बुलगुर एक प्रकार का अनाज, नाशपाती जौ, और कूसकूस पौष्टिक, कम

केले : केले पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत हैं और गुर्दे के लिए आहार को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। अनानास किडनी के लिए अनुकूल फल है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य उष्णकटिबंधीय फलों की तुलना में बहुत कम पोटेशियम होता है।

डेयरी : डेयरी उत्पादों में उच्च मात्रा में फॉस्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन होते हैं और इन्हें गुर्दे के आहार में सीमित किया जाना चाहिए। दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के बावजूद, इसकी फास्फोरस सामग्री गुर्दे की बीमारी वाले लोगों की हड्डियों को कमजोर कर सकती है।

शब्द सामर्थ्य - 71

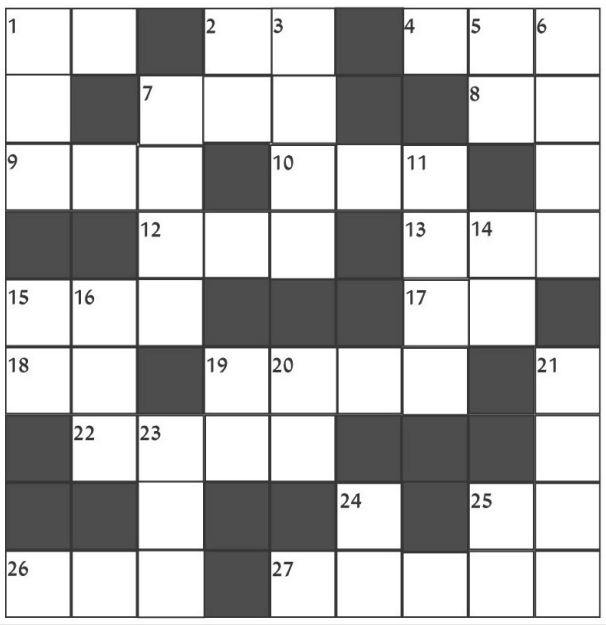
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. कतार, क्रम, पांत 2. लज्जत, जायका 4. कारण, वजह 7. सुंदर प्रतीत होना, सुखद होना 8. घोड़े आदि का मल 9. अक्सर, ज्यादातर 10. चक्की में पीसना, मसलना, कुचलना 12. धनुष, फौजी टुकड़ी 13. आभूषण, जेवर 15. लहरों का चक्कर, जलावर्त, भ्रमर 17. बायां, विरुद्ध 18. गाना, नगमा 19. लाचार, विवश 22. नमन, प्रणाम 25. चौकी, थाना 26. इकरार, समझौता, ठेका 27. अधिकार होना, सामर्थ्य होना (मुहा.)।

ऊपर से नीचे

1. एक प्रदेश जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है 2. हविर्दान के समय उच्चारित एक शब्द, भष्म 3. दन-दन करते हुए 5. बलशाली, बलवाला 6. परिवर्तित करना, पहले से भिन्न हो जाना 7. चांद, चंद्रमा, रजनीश 11. अप्रिय, अरुचिकर 14. मैं का बहुवचन 15. भंगेड़ी, भंग करने वाला, झाड़ू लगाने तथा मैला साफ करने वाली 16. मातृभूमि, स्वदेश 19. मक्खन, माखन 20. बुढ़ापा, धन, ज्वर 21. टालना, हटाना, बहाना करके हटाना 23. सीमा, हद 24. सौ का पाचंवा हिस्सा 25. घोड़े के पैरों में लगाने का लोहे का टुकड़ा, पौधे आदि का डंठल।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 70 का हल

वि	ज	य	■	ब	नि	या	■	दे
वा	■	ती	त	र	■	रा	जी	व
ह	मा	म	■	स	प	ना	■	ता
■	न	■	■	■	टा	■	■	■
दा	व	त	■	वि	ना	श	■	अ
य	■	ह	त्या	■	■	ह	र्जा	ना
रा	ह	त	■	न	ज	र	■	व
■	वा	■	■	■	मी	■	ना	श्य
दु	ला	रा	■	जा	न	की	■	क

शूर्पणखा बनने में रोज लगते थे 4 घंटे : रकुल प्रीत

साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन और रणबीर कपूर के राम अवतार से सजी ये फिल्म वाल्मीकि के महाकाव्य और रामचरितमानस पर आधारित है। फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अब इस यात्रा को लेकर एक बेहद भावुक नोट साझा किया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए फिल्म के निर्माताओं का दिल से आभार व्यक्त किया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर रामायण की शूटिंग के दौरान की अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में वो सेट पर अपना मेकअप कराती और शूटिंग के लिए तैयार होती दिख रही हैं। एक भावुक पोस्ट लिखते हुए रकुल ने लिखा, ये मेरे लिए बेहद खास सफर रहा है। सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही इस महान कहानी को इतने बड़े पैमाने पर पर्दे पर जीवंत होते देखना और इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से जुड़ना उनके लिए गर्व का पल है।

रकुल ने पूरी कास्ट और क्रू का धन्यवाद करते हुए निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी की जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा कि इन दोनों महान फिल्मकारों ने एक बड़ा सपना देखा और उसे पर्दे पर सच कर दिखाया। भारत से इस महान कहानी को पूरी दुनिया के सामने इतने भव्य और असाधारण तरीके से पेश करने की उनकी मेहनत और इच्छाशक्ति ने पूरे सफर के दौरान सभी को गहराई से प्रेरित किया है। राकुल ने अपनी मेकअप और कॉस्ट्यूम टीम की जमकर सराहना करते हुए बताया कि उन्हें शूर्पणखा के लुक में ढालने के लिए टीम हर दिन 4 घंटे तक कड़ी मेहनत करती थी। उन्होंने बताया कि आज इस लुक को मिल रही सभी तारीफों का असली हकदार उनकी टीम का हुनर ही है। इस प्रोजेक्ट के लिए आभार जताते हुए रकुल ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ऐसा पल है, जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराता है।

निक जोनास ने तमिल गाने पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल

प्रियंका चोपड़ा के विदेश पति निक जोनास का कॉन्सर्ट से पहले किसी बॉलीवुड गाने पर झूमना कोई नई बात नहीं है। अक्सर वो स्टेज पर उतरने से पहले हिंदी गानों से माहौल जमाते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने भारतीय फैंस को सरप्राइज दिया है। निक अपने भाइयों जो और केविन जोनस के साथ मशहूर युवा संगीतकार साई अभ्यंकर के वायरल तमिल इंडी हिट गाने राधिमा पर धमाकेदार डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक प्यारे वीडियो में निक अपने भाइयों के साथ राधिमा गाने पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। इस क्लिप के जरिए यूं तो उन्होंने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं, लेकिन उनके गाने के चुनाव ने हर किसी का दिल जीत लिया। तमिल गाने के कंपोजर साई अभ्यंकर भी निक का डांस देखकर खुश हो गए। उन्होंने निक के पोस्ट पर लाल दिल वाला इमोजी शेयर करते हुए प्यार से भाई लिखा। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद निक को भारत में नेशनल जीजू कहा जाने लगा था और अब फैंस ने उन्हें एक नया प्यार भरा नाम दिया है। गाने के बोल तंगामान पय्यन का मतलब गोल्ड बॉय है। फैंस ने इस नाम को निक से जोड़ दिया है।

रितेश देशमुख ने किया तेलुगु सिनेमा का रुख, पोथिनेनी की फिल्म आरएपीओ में शामिल

बॉलीवुड और मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुके अभिनेता रितेश देशमुख अब तेलुगु सिनेमा में भी अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वह दक्षिण भारतीय अभिनेता राम पोथिनेनी की आगामी फिल्म आरएपीओ23' से तेलुगु फिल्म जगत में पदार्पण करेंगे। इस फिल्म में रितेश मुख्य अभिनेता के रूप में नजर आएंगे। खास बात यह है कि वह राम पोथिनेनी के साथ फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। निर्माताओं ने आधिकारिक रूप से इस परियोजना की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही फिल्म का पहला वीडियो भी जारी किया गया है। रितेश देशमुख ने हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने अभिनय तथा हास्य भूमिकाओं से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। अब तेलुगु फिल्म के माध्यम से वह अपने अभिनय का नया आयाम पेश करने के लिए तैयार हैं। आरएपीओ23' को लेकर जारी पहली झलक से फिल्म की शुरुआत को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म के पहले चरण की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। इसका निर्माण कृष्णा पोथिनेनी, रैपो सिनेमैटिक्स के बैनर तले कर रहे हैं। फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ रितेश देशमुख और मुख्य अभिनेत्री के रूप में संयुक्ता नजर आएंगी। रितेश का इस फिल्म से जुड़ना इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि वह अभिनय के साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। ऐसे में दर्शकों को पर्दे पर उनकी नई भूमिका देखने के साथ-साथ उनके निर्देशन कौशल की झलक भी मिलेगी। आरएपीओ23' की कहानी और अन्य कलाकारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। निर्माताओं ने फिल्म की प्रदर्शन तिथि की भी घोषणा नहीं की है। हालांकि, शूटिंग शुरू होने के साथ ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का काम आगे बढ़ गया है। रितेश देशमुख के तेलुगु सिनेमा में प्रवेश से उनके प्रशंसकों को एक नई भाषाई फिल्म में उनका अभिनय देखने का अवसर मिलेगा। अब दर्शकों की नजर फिल्म की अगली झलक, कहानी और प्रदर्शन तिथि की आधिकारिक घोषणा पर रहेगी।

मुझे 16 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि अभिनेत्री बनूंगी : दीपिका पादुकोण



बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बताया कि उन्हें 16 साल की उम्र में पता चल गया था कि वह अभिनेत्री बनना चाहती थीं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस समय बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में से एक हैं। जब उन्होंने ट्रिपल एक्स - द रिटर्न ऑफ जेंडर केज के साथ हॉलीवुड में कदम रखा, तो दीपिका द एलेन डीजेनेरेस शो में भी नजर आईं। एलेन से बात करते हुए बाजीराव मस्तानी फिल्म की अभिनेत्री ने अपने पिता प्रकाश पादुकोण के बैडमिंटन करियर के बारे में खुलकर बात की।

दीपिका ने बताया कि उन्होंने भारत में ऐसे समय में बैडमिंटन खेला, जब कोई भी प्रोफेशनल तौर पर बैडमिंटन नहीं खेलता था। उस समय हर कोई डॉक्टर या वकील बनना चाहता था, लेकिन वे एक खिलाड़ी थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की इच्छा जताई थी, तो अभिनेत्री ने जवाब दिया कि मैं ऐसा करके उन्हें खुश कर सकती थी, लेकिन वे हमेशा यही कहते थे कि अपने दिल की सुनो। अभिनय के प्रति अपना प्यार जताते हुए दीपिका ने बताया कि 16 साल की उम्र में ही उन्हें पता चल गया था कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कैमरे के सामने रहना उन्हें बेहद खुशी देता है। दीपिका ने एलेन को यह भी बताया कि एक बार उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करने के लिए अपनी मां से 10,000 रुपए उधार लिए थे। पैसे मांगते समय अभिनेत्री ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि वह उनके पैसे लौटा देंगी और उन्हें गौरवान्वित भी करेंगी।

दीपिका ने बताया कि एक दिन मैंने अपनी मां को बिठाया और कहा कि क्या मैं आपसे 10,000 रुपए उधार ले सकती हूं? मुझे पोर्टफोलियो शूट करने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने उनसे कहा कि एक दिन मैं उन्हें गौरवान्वित करूंगी और कभी न कभी उनके पैसे भी लौटा दूंगी।

साल 2007 में शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद, दीपिका कई प्रमुख फिल्मों का हिस्सा बनीं, जिनमें ये जवानी है दीवानी (2013), चेन्नई एक्सप्रेस (2013), गोलियों की रासलीला राम-लीला (2013), पीकू (2015), बाजीराव मस्तानी (2015), पद्मावत (2018), छपाक (2020), पठान (2023), जवान (2023) और कल्कि 2898 एडी (2024) शामिल हैं।

हॉरर फिल्म जानी दुश्मन में खौफ फैलाएंगी भूमि पेडनेकर



अभिनेत्री भूमि पेडनेकर एक बार फिर अपने अभिनय से दर्शकों को चौंकाने की तैयारी में हैं। अपने फिल्मी करियर में अलग-अलग तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने वाली भूमि अब मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म जानी दुश्मन - डर के आगे मौत है में नजर आएंगी। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के साथ ही इसका पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। फिल्म का निर्देशन अरशद सैयद करेंगे, जबकि इसका निर्माण टी-सीरीज और प्रभलीन संधू की ऑलमाइटी मोशन पिक्चर के सहयोग से किया जाएगा।

फिल्म का पहला पोस्टर एक शांत महिला और उसके आसपास मौजूद डरावने वातावरण को दर्शाता है। पोस्टर से फिल्म की रहस्यमयी और भयावह दुनिया की झलक मिलती है। हालांकि, फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कहानी मां-बेटी के भावनात्मक रिश्ते के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इसमें पारिवारिक संबंधों के साथ डर और रहस्य का अनूठा मेल देखने को मिलेगा।

फिल्म के पोस्टर के साथ निर्माताओं ने दर्शकों के लिए खास संदेश भी साझा किया है। इसमें लिखा गया है, डर तो बहुत देखा होगा, अब खौफ महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। इस संदेश ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

इस फिल्म की एक खास बात यह भी है कि इसके लिए चर्चित अलौकिक घटनाओं पर आधारित शृंखला भय - द गौरव तिवारी मिस्ट्री की रचनात्मक टीम एक बार फिर साथ आई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले एक्शन और दृश्य-कौशल निर्देशक पीटर पेड्रेरो भी इस परियोजना से जुड़े हैं। उनके जुड़ने से फिल्म के डरावने दृश्यों और तकनीकी पक्ष को खास रूप मिलने की उम्मीद है।

निर्माताओं के अनुसार, जानी दुश्मन - डर के आगे मौत है को वर्ष 2027 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। भूमि पेडनेकर के नए अवतार और मनोवैज्ञानिक डर के साथ मां-बेटी के रिश्ते की कहानी को बड़े पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए दिलचस्प अनुभव हो सकता है।



सरकारी स्कूलों के बच्चों को किए स्वेटर वितरित

नगर संवाददाता

देहरादून। संकल्प शिक्षण एवं कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट ठाकुर रवि सिंह नेगी के संरक्षण में समाज सेवक मनोज कपूर, श्रीमती सरोज चौहान, अशोक वर्धन सिंह, तथा राजीव पंवार के सहयोग से प्राइमरी स्कूल सुंदर वाला तथा प्राइमरी स्कूल थाना थानों रोड सोडा के बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था की संस्थापक महासचिव श्रीमती अनीता नेगी ने कहा कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है और सरकारी स्कूल के मूल सुविधाओं से वंचित इन बच्चों में भी हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। इनका ख्याल रखना और उनको उचित अवसर प्रदान करना हम सब का कर्तव्य है।

कार्यक्रम का संचालन मनोज कपूर द्वारा किया गया। अन्य लोगों के अलावा कार्यक्रम में रवि सिंह नेगी, अशोक वर्धन सिंह, मनोज कपूर, राजीव पवार श्रीमती अनीता नेगी, श्रीमती संगीता गैरोला और श्रीमती बीना पवार उपस्थित थे।

नवजात के देखभाल की जानकारियां दीं

पौड़ी (आरएनएस)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित नवजात शिशु सप्ताह के तहत वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. हितेन जगपांगी ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात को जन्म के तुरंत बाद जरूरी देखभाल, कंगारू मदर केयर, टीकाकरण, संक्रमण से बचाव और नवजात में खतरे के लक्षणों की समय पर पहचान की जानकारियां दीं। सीएमओ डॉ. मेघना असवाल ने बताया कि शिशु सप्ताह 21 तक आयोजित होगा। जिसमें स्वास्थ्य कर्मी लोगों को संस्थागत प्रसव, स्तनपान के तरीके व महत्व, नवजात शिशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच और उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं की समयबद्ध पहचान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बताया कि पूर्व में सभी स्वास्थ्य केंद्रों के सीएचओ, एएनएम, चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग अधिकारियों को शिशुओं से जुड़ी जानकारियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

सू- दोकू क्र.71

	7			4		3		
2			3			9		4
	6			2				
3		1			7		4	
	2			1			6	
8			9		4			1
		2		3		7		
1			7		2	4		3
	5	3		8			7	2

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.70 का हल

9	2	8	3	1	5	7	4	6
4	1	6	8	9	7	2	5	3
7	3	5	4	6	2	8	1	9
2	7	3	9	8	1	4	6	5
5	4	1	6	7	3	9	2	8
6	8	9	2	5	4	1	3	7
3	6	2	7	4	9	5	8	1
8	5	7	1	2	6	3	9	4
1	9	4	5	3	8	6	7	2

18 हजार रुपये मानदेय मांग को लेकर सीईओ कार्यालय में गर्जी भोजनमाता

रुद्रपुर(आरएनएस)। न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय, स्थायीकरण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भोजनमाताओं ने मंगलवार को प्रगतिशील भोजनमाता संगठन के बैनर तले मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन भोजनमाताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य शिक्षा अधिकारी पुष्कर टम्टा को सौंपा।

भोजनमाताओं ने नेशनल हाईवे किनारे धरना दिया। इसके बाद रैली निकालते हुए सीईओ कार्यालय पहुंचीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में वर्षों से बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें मात्र तीन हजार रुपये के करीब मानदेय दिया जा रहा है।महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भोजन बनाने के अलावा उनसे सफाई कर्मचारी, माली और चौकीदार तक के काम कराए जाते हैं। परीक्षा, प्रशिक्षण, कागजी कार्य और चुनाव ड्यूटी में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं, अतिरिक्त काम का अलग से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। चुनाव ड्यूटी के दौरान भोजन का उचित भुगतान भी नहीं किया जाता है।

भोजनमाताओं को नियमित अवकाश की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। भोजनमाताओं ने कहा कि कई महिलाएं 20 वर्षों से अधिक समय से विद्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। विद्यालयों के विलय अथवा छात्र संख्या कम होने का हवाला देकर उन्हें काम से हटा दिया जाता है। कई बार मांग उठाने और ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन में भोजनमाताओं का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने, स्थायी नियुक्ति देने, साप्ताहिक, आकस्मिक और बीमारी अवकाश के साथ पीएफ और ईएसआई की सुविधा लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा विद्यालय बंद होने या विलय की स्थिति में नजदीकी विद्यालय में समायोजित करने, मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खातों में करने, लंबित मानदेय, वर्दी और बोनस का समय से भुगतान करने की मांग उठाई गई। भोजनमाताओं ने प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित रसोई, गैस और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, भेदभाव व उत्पीड़न पर कार्रवाई करने, अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा तैयार भोजन पर रोक लगाने तथा संगठन के प्रतिनिधियों के साथ नियमित वार्ता करने की भी मांग की।

पंजीकृत श्रमिकों को बांटे किट

पिथौरागढ़(आरएनएस)। नगर के त्रिपुरादेवी कैंप कार्यालय में श्रम विभाग की ओर से श्रमिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक फकीर राम टम्टा ने किया। टम्टा ने पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवारों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वच्छता और पोषण से संबंधित सामग्री किट वितरित किए। टम्टा ने कहा प्रदेश सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उप श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने बताया शिविर में कुल 250 श्रमिकों को किट बांटे गए हैं। कहा दूरस्थ क्षेत्रों के श्रमिकों की सुविधा को देखते हुए आगामी दिनों में न्याय पंचायत स्तर पर किट वितरित किए जाएंगे। इस दौरान जिला श्रम अधिकारी प्रदीप बिष्ट, समाज कल्याण अनुश्रवण समिति के सदस्य दीपक नौलिया मौजूद रहे।

दो साल से टूटी पाइपलाइन, प्लास्टिक के पाइपों से हो रही आपूर्ति

चमोली (आरएनएस)। जल संस्थान की नंदकेशरी-तलसारी पेयजल योजना की पाइपलाइन दो साल से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में ग्राम पंचायत कोठी में प्लास्टिक के पाइप जोड़कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मगर इससे आए दिन आपूर्ति बाधित हो जाती है। ग्रामीणों को स्रोतों से पानी भरना पड़ता है।

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से योजना की मरम्मत कराने और नई योजना बनाने की मांग की।ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी, लोकपाल रावत, देवी दत्त, भुवन चंद्र, गोविन्द प्रसाद, नवीन चंद्र, बलवंत सिंह, मुन्ना, महेशानंद, अमूल, गोलू और जगदीश चंद्र ने बताया कि दो साल पहले लोनिवि की नंदकेशरी-धरातल्ला सड़क कटिंग के दौरान योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।

वहीं सड़क के मलबे में एक किमी से अधिक पाइपलाइन दब गई। इसके बाद विभाग ने प्लास्टिक के पाइप जोड़कर अस्थायी व्यवस्था से पानी की आपूर्ति शुरू की। उन्होंने डीएम से योजना की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि नंदकेशरी श्रीनंदा राजजात का मुख्य पड़ाव है जहां गढ़वाल और कुमाऊं की देव डोलियों व छतोलियों का मिलन होता है। ग्रामीणों ने राजजात के मद्देनजर नई पेयजल योजना और टंकी बनाने की भी मांग की।

वहीं जल संस्थान के सहायक अभियंता डीआर मौर्य ने बताया कि सड़क कटिंग से पाइपलाइन मलबे में दब गई थी। फिलहाल प्लास्टिक की अस्थायी लाइन से आपूर्ति की जा रही है। नुकसान का आकलन कर डेढ़ साल पहले लोनिवि को इस्टीमेट भेजा गया था लेकिन क्षति की धनराशि अभी नहीं मिली है। विभाग को दोबारा पत्र भेजा जाएगा।

धान का बकाया भुगतान, डीएपी खाद और मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन

रुद्रपुर(आरएनएस)। धान खरीद का बकाया भुगतान, डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता और ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिलेभर के किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और तीनों समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि वे पहले ही प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ती कृषि लागत और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अपनी जायज मांगों के लिए सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

किसानों ने बताया कि सरकारी केंद्रों पर धान खरीद हुए करीब डेढ़ महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अनेक किसानों को उपज का भुगतान नहीं मिला है। उन्होंने बकाया भुगतान तत्काल कराने और देरी के कारणों की जांच की मांग की। किसानों ने कृषि सीजन में डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकारी खाद केंद्रों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के साथ कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निष्पक्ष सर्वे कराकर सभी पात्र किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा देने की मांग की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू, विक्रमजीत सिंह, जगतार सिंह बाजवा, मोहन खेड़ा, अमरीक सिंह, मनजिंदर सिंह भुल्लर, गुरसेवक सिंह मोर, अनिल सिंह राणा, गुरविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह बिल्ला, गुरसेवक नामधारी और तेजपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

निर्माणाधीन मकान से बिजली की तारे चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने निर्माणाधीन मकान से बिजली की तारें चोरी कर सीसीटीवी कैमरे को तोड दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवाजी मार्ग निवासी अमित तोमर ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। आज जब वह निर्माणधीन मकान में पहुंचा तो देखा कि वहां से तारों के बंडल गायब थे लोहे के कॉपर जीआई का सामान गायब था तथा वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड दिया गया। सीसीटीवी कैमरें की रिकार्डिग के अनुसार यह काम किसी महिला का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

आबादी की गिनती से खुलेंगी 'परतें'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

का आधार बन सकते हैं। इस बार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जाति संबंधी जानकारी का संग्रह भी है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामान्य जनगणना के दायरे में व्यापक जातिगत गणना शामिल की गई है। उत्तराखंड में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश में विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का अनुमान लगाने का आधार मिलेगा। आरक्षण, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी जैसे सवालों पर नई बहस शुरू हो सकती है।

राजनीतिक दलों के लिए भी यह आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग किस क्षेत्र में कितना प्रभाव रखता है, किन इलाकों में सामाजिक संरचना किस तरह बदल रही है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, इन सवालों के जवाब भविष्य की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जनगणना में जाति की जानकारी जुटाना और उसके आधार पर राजनीतिक या नीतिगत फैसले लेना दो अलग-अलग विषय हैं। आंकड़े आने के बाद उनका विश्लेषण और उपयोग अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा।

उत्तराखंड की जनसांख्यिकी का एक बड़ा सवाल पहाड़ और मैदान के बीच असंतुलन है। पर्वतीय जिलों में कई क्षेत्रों में आबादी का दबाव कम हो रहा है, जबकि मैदानी जिलों में शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है।इस बदलाव का असर केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। घरों की जियो टैगिंग, डिजिटल मानचित्र और मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। लोग स्वयं भी ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।

पहले 'पर्दे' के पीछे अब 'मीडिया' के..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

किया? यदि इन दस्तावेजों में वास्तव में कोई महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उन्हें संबंधित जांच एजेंसी और अदालत के समक्ष रखने का रास्ता मौजूद था। मीडिया के सामने निजी बातचीत के पन्ने रखकर एक मृत युवती की छवि पर सवाल उठाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इन चैट की प्रामाणिकता, पूर्णता और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है। केवल कुछ बातचीत के अंशों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

अंकिता भंडारी प्रकरण की सबसे संवेदनशील कड़ी कथित वीआईपी की भूमिका रही है। घटना के बाद से ही प्रदेश में यह सवाल उठता रहा कि आखिर वनंत्रा रिजार्ट में किसे विशेष सेवा देने का दबाव बनाया जा रहा था? उस कथित वीआईपी की पहचान क्यों सामने नहीं आई? अंकिता के माता-पिता आज भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। यही वह बिंदु है जहां यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह जाता, बल्कि सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही से जुड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाता है। विनोद आर्य की प्रेस वार्ता में उनके अधिवक्ता की ओर से वीआईपी की भूमिका से इनकार किए जाने और मामले को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताने से यह बहस फिर तेज हुई है। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि जांच में किसी भी संभावित पहलू को छोड़ा न जाए। उनका सवाल है कि जब उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है तो उसके मामले से जुड़े सभी संदिग्ध पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल क्यों नहीं होनी चाहिए?

इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और जांच एजेंसियों के सामने भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक ओर अदालत से दोषसिद्धि हो चुकी है, दूसरी ओर वीआईपी की कथित भूमिका और जांच के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब विनोद आर्य की प्रेस वार्ता और उनके द्वारा सार्वजनिक की गई चौट ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। सरकार के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई अब केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है। यह उत्तराखंड की सामूहिक संवेदना और सत्ता से जवाब मांगने का प्रतीक बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सीबीआई जांच में विनोद आर्य की भूमिका, घटना के समय उनकी गतिविधियों, काल डिटेल और सार्वजनिक की गई चौट के स्रोत की पड़ताल होगी? क्या कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर भी कोई ठोस निष्कर्ष सामने आएगा?

दरअसल, अंकिता हत्याकांड में अब एक नई लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। एक तरफ दोषसिद्ध बेटे के बचाव में पिता के दावे हैं तो दूसरी तरफ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता के अनुत्तरित सवाल। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है और अपनी बात खुद नहीं कह सकती। उसकी निजी जिंदगी को बहस का विषय बनाने के बजाय उन सवालों के जवाब तलाशे जाने चाहिए, जिनके लिए उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है। अंकिता को न्याय केवल दोषियों की सजा से पूरा नहीं होगा, बल्कि उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर अनुत्तरित सवाल का निष्पक्ष और विश्वसनीय जवाब सामने आने से होगा।

अंकिता भंडारी प्रकरणः निजी व्हाट्सऐप बातचीत सार्वजनिक करने में मुकदमा दर्ज करने की मांग

संवाददाता

देहरादून। अंकिता भण्डारी प्रकरण में मृतका की निजी व्हाट्सएप बातचीत सार्वजनिक करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।



आज यहां हिमांशु पुंडीर प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर एकत्रित हुए जहां पर उन्होंने प्रदर्शन कर एसएसपी को सम्बाधित ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के इतिहास की एक अत्यंत संवेदनशील और पीड़ादायक घटना है। इस मामले ने पूरे प्रदेश की जनभावनाओं को झकझोरा है। ऐसे में पीड़िता की गरिमा, निजता और सम्मान की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। 15 नवंबर 2026 को हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद आर्य द्वारा अंकिता भंडारी की बताई जा रही हजारों पृष्ठों की निजी व्हाट्सऐप बातचीत सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई। इस सामग्री के आधार पर मृतका के व्यक्तिगत संबंधों, निजी जीवन और पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर भी सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित करने का औचित्य क्या है? ये दस्तावेज किस स्रोत से प्राप्त किए गए? क्या इन्हें सार्वजनिक करने की विधिवत अनुमति ली गई थी और क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार किसी महिला की निजी जानकारियों को सार्वजनिक करके उसके चरित्र एवं व्यक्तिगत जीवन को चर्चा का विषय बना दे? भारत की न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि यौन अपराध की पीड़िता की पहचान और उससे जुड़ी संवेदनशील निजी जानकारियों की गोपनीयता तथा गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए।

किसी महिला के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद उसकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक करना उसकी गरिमा और निजता पर गंभीर आघात है। इस मामले में सार्वजनिक की गई सामग्री और उसके प्रदर्शन की परिस्थितियों की जांच कर यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या कोई दंडनीय अपराध किया गया है। यदि विनोद आर्य के पास इस प्रकरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य अथवा जानकारी थी, तो उसे सक्षम जांच एजेंसी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी बातचीत प्रदर्शित कर उसके आधार पर मृतका के व्यक्तिगत जीवन पर सार्वजनिक चर्चा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। विनोद आर्य द्वारा 15 नवंबर 2026 को हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता भंडारी की निजी बातचीत और व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक किए जाने के मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए। सार्वजनिक की गई कथित व्हाट्सऐप चैट और दस्तावेजों के स्रोत, उनकी प्रमाणिकता तथा उन्हें प्राप्त करने और सार्वजनिक करने की अनुमति की जांच की जाए। किसी जघन्य अपराध की पीड़िता रही महिला की निजी जानकारियों को सार्वजनिक करना उसकी गरिमा एवं निजता का गंभीर उल्लंघन है। अतः इस पूरे कृत्य की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विनोद आर्य के विरुद्ध उचित कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रदर्शित दस्तावेजों और संबंधित डिजिटल सामग्री को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया जाए, ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा साक्ष्य नष्ट होने की आशंका न रहे। इस मामले में किसी भी प्रकार के राजनीतिक या अन्य दबाव से मुक्त रहकर कार्रवाई की जाए तथा शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

रुद्रपुर में स्कूली-यात्री वाहनों की जांच, 88 चालान और 15 सीज

रुद्रपुर(आरएनएस)। स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूली व यात्री वाहनों के खिलाफ विशेष सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है।

अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जांच कर 88 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 15 वाहनों को सीज कर दिया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखंड के निर्देश और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर 16 से 22 नवंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रुद्रपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्कूली बसों, वैन, कैब और यात्री वाहनों की जांच की।

परिवहन कर अधिकारी आशुतोष डिमरी, आनंद प्रकाश गुप्ता, तारकेन्द्र वैष्णव और मुकुल अग्रवाल की प्रवर्तन टीमों ने कार्रवाई की। जांच में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के 22, बिना टैक्स के 25, बिना बीमा के 10 और बिना फिटनेस के आठ वाहनों के चालान किए गए। इसके अलावा पांच वाहन बिना सीसीटीवी कैमरे, तीन बिना परमिट, पांच बिना अग्निशमन यंत्र और दो बिना प्राथमिक उपचार पेटिका के मिले। ओवरलोडिंग समेत अन्य उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की गई।

छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को अपराधों के प्रति किया जा रहा है जागरूक

हमारे संवाददाता

उत्तरकाशी। नशा, बाल, महिला एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता को सशक्त बनाने तथा सामाजिक बुराइयों एवं अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा जनपदभर में निरंतर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

एएचटीयू द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज जुणगा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, च्च्ब्ब् अधिनियम तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी एवं सामाजिक विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। टीम द्वारा विद्यार्थियों को आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की उपयोगिता से अवगत कराते हुए उत्तराखण्ड पुलिस ऐप एवं गौरा शक्ति फीचर के माध्यम से उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं एवं उनके उपयोग की जानकारी दी गई।

विद्यार्थियों को सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने तथा



ऑनलाइन किसी भी प्रकार की निजी जानकारी साझा करते समय सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त एएचटीयू टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचकर अभिभावकों एवं ग्रामीणों को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

ग्रामीणों को बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों एवं अपराधों की रोकथाम में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि, शोषण अथवा अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

नवनियुक्त सीडीओ दीपक सैनी ने संभाला कार्यभार

संवाददाता

देहरादून। नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी ने कार्यभार सम्भालते ही विकास कार्यो को गति देने का संकल्प किया।



आज यहां जनपद देहरादून में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीपक सैनी ने आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के उपरांत उन्होंने शासन द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी के प्रति आभार व्यक्त किया और जनपद के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं का खुलकर खाका खींचा। पदभार ग्रहण करते ही मीडिया से बातचीत में श्री सैनी ने कहा, ''सर्वप्रथम, मैं उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के रूप में कार्य करने का यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।''

उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना होगी। अपने आगामी कार्यकाल के लिए श्री सैनी ने पांच सूत्रीय प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की है। ग्रामीण विकास एवं आजीविका संवर्धन-स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,

❑विकास कार्यों को गति देने का किया संकल्प

स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता-सभी निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना, कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करते हुए लंबित विकास कार्यों को त्वरित गति देना। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाएँ-ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना तथा पेयजल, स्वच्छता व बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना। जनभागीदारी और जवाबदेही-आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, नियमित फील्ड विजिट करना और ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी समीक्षा करना। सतत एवं समावेशी विकास-देहरादून के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण-संवेदनशील विकास, आपदा-सुरक्षा और स्थानीय रोजगार सृजन पर विशेष फोकस।

नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी ने कहा ''मेरा प्रयास रहेगा कि विकास का सकारात्मक प्रभाव आम नागरिक के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सभी विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ मिलकर 'टीम भावना', पूरी पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यशैली के साथ देहरादून जनपद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे।

शिक्षा निदेशालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने खून से लिखा पत्र

हमारे संवाददाता

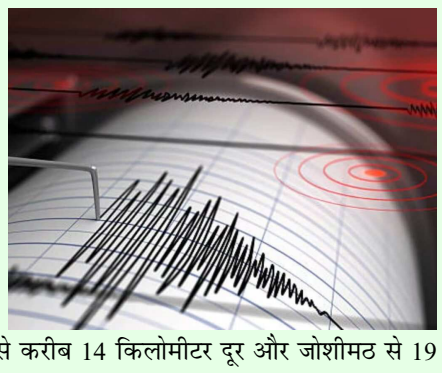
देहरादून। उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। संगठन के अनुसार, 4 जून से शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, देहरादून में प्रशिक्षित बेरोजगार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के 168दिन पूरे हो चुके हैं, जबकि 153वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी है। वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होने अपनी मांगों के लेकर आज शिक्षा मंत्री के नाम खून से लिखा पत्र जारी किया है।

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय ने कहा कि यह संघर्ष केवल बेरोजगार युवाओं की रोजी-रोटी का सवाल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की स्थिति और बच्चों के सर्वांगीण विकास से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार खेल महोत्सवों के माध्यम से प्रदेश के नौनिहालों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अनेक सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदों की कमी बनी हुई है। विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों को खेल प्रशिक्षण और नियमित शारीरिक शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।

पाण्डेय ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने, अनुशासन विकसित करने तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में योग्य शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। केवल खेल आयोजन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालय स्तर पर नियमित प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र खत्री प्रदेश प्रभारी अर्जुन लिंगवाल के साथ भुवनेश बिष्ट, संजय कोरंगा, भुवनेश बिष्ट, महेश नेगी,हरेन्द्र खत्री,विनोद रावत, दीपेंद्र भंडारी दर्जनों शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार उपस्थित रहे।

भूकंप से दो बार दहली धरती, लोगों में दहशत

हमारे संवाददाता



चमोली/रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सबसे बड़ी खबर चमोली से आई है। आज सुबह चमोली में आधे घंटे के अंदर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप सुबह 10 बजकर 21 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। इसका केंद्र गोपेश्वर से करीब 14 किलोमीटर दूर और जोशीमठ से 19 किलोमीटर दक्षिण में जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। इसके झटके चमोली के साथ-साथ पौड़ी और टिहरी गढ़वाल तक महसूस किए गए, लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। ठीक 31 मिनट बाद सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर फिर से 2.8 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, इसका केंद्र जोशीमठ से 24 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में 5 किलोमीटर गहराई में था। राहत की बात ये है कि अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन जोशीमठ जैसे संवेदनशील इलाके में दो बार झटके आने से लोगों में दहशत का माहौल है।

टपकेश्वर बाईपास मार्ग के निर्माण को लेकर मंत्री ने किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर में प्रस्तावित बाईपास मार्ग के निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित बाईपास मार्ग की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों से निर्माण से संबंधित प्रस्ताव एवं सर्वे कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टपकेश्वर बाईपास मार्ग से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने और सर्वे की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने सर्वे



कार्य के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी राय और सुझावों को भी शामिल करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही के साथ ही स्थानीय लोगों का आवागमन भी निरंतर बना रहता है। ऐसे में बाईपास मार्ग का निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बनने से टपकेश्वर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी तथा आवागमन अधिक सुगम और व्यवस्थित होगा। इस दौरान पर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, विष्णु गुप्ता, सारिका खत्री, मनोज क्षेत्री, आचार्य विपिन जोशी एवं लोक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता चंद्रकला सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव

हमारे संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग का विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। उन्होंने परियोजना में कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया दिया और निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।



मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरण अभी भी लंबित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे प्रकरणों को अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही सम्बन्धित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों। उन्होंने उत्तरकाशी में सम्बन्धित भूमि का कब्जा भी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, आरओ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पंकज सिंह एवं बीआरओ के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।